

No. 1/5/2024-E.II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

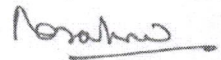
North Block, New Delhi
Dated the 21st October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees-
effective from 01.07.2024.**

The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum No. 1/1/2024-E.II (B) dated 12th March, 2024 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the rates of Dearness Allowance payable to Central Government employees, shall be enhanced from **50% to 53% of the Basic Pay with effect from 1st July, 2024.**

2. The term Basic Pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.
3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).
4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.
6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.



(Abhimanyu Sahoo)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.



प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक : GN : 051120240103942

GEN No : 2062/2024-2025

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार सरकार,
पटना- 800015 .

विषय : अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी (भा0प्र0से0, भा0पु0से0 एवं भा0व0से0) एवं पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 53% की दर से महँगाई भत्ता का भुगतान करने के संबंध में।

प्रसंग : वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं0-1/5/2024-E-II (B) दिनांक- 21.10.2024

महाशय / महाशया,

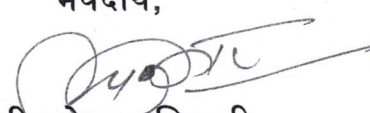
उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं0-1/5/2024-E-II (B) दिनांक- 21.10.2024 के द्वारा केंद्र सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर, मूल वेतन का 50% से बढ़ाकर 53% की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त आदेश के आलोक में अनुरोध है कि राज्य अवस्थित सभी कोषागारों को अपने स्तर से निर्देश देने की कृपा की जाय कि राज्य सरकार के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के कार्यरत सभी पदाधिकारियों (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी) तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के माननीय न्यायाधीशों को दिनांक - 01.07.2024 के प्रभाव से मूल वेतन का 53% की दर से महँगाई भत्ते का भुगतान किया जाय। इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को अलग से वेतन पुर्जा प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी।

कृपया इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

अनु०- यथोपरि।

भवदीय,


वरीय लेखा अधिकारी
बिहार, पटना।

ज्ञापक :-

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. महानिबंधक, माननीय पटना उच्च न्यायालय,
पटना- 800 028
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार
सरकार, पटना- 800 015
3. सचिव, गृह विभाग (आरक्षी-शाखा), बिहार सरकार,
पटना -800 023
4. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

वरीय लेखा अधिकारी
बिहार, पटना।